डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 जनवरी, 2025, डिस्पेच दिनांक 16 जनवरी, 2025

| वर्ष 68 | अंक 16 | भोपाल | 16 जनवरी, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

श्री अमित शाह ने NCOL की समीक्षा बैठक में सहकारी ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने पर दिया जोर

देश में सभी PACS को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़ ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान चलाया जाये

ऑर्गेनिक उत्पादों के स्रोत और उत्पादों की शुद्धता का पर ध्यान देना NCOL की प्राथमिकता हो

ऑर्गेनिक उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग और उचित मूल्य मिलने से किसान ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित होंगे

NCOL द्वारा उत्तराखंड के किसानों से खरीदे गए धान से किसानों 10% से 15% तक का अधिक लाभ हुआ

सभी PACS ऑर्गेनिक उत्पादों और बीजों की बिक्री के केन्द्र बनें

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में नेशनल कॉपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता मंत्रालय के सचिव श्री आशीष कुमार भूटानी, सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव श्री पंकज बंसल, नेशनल कॉपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मिनेश शाह और नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के. वी. सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

बैठक के दौरान श्री अमित शाह ने कहा कि देश में सभी PACS को ऑर्गेनिक मिशन से जोड़कर ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने का अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों के स्रोत और उत्पादों की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। श्री अमित शाह ने कहा कि NCOL को अपने "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के तहत किसानों से ग्राहकों तक प्रामाणिक जैविक उत्पादों की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को शुद्ध प्रमाणिक जैविक उत्पाद बाजार मे सुलभ हो सकें इसमे NCOL को प्रत्येक 'भारत ऑर्गेनिक्स' उत्पाद के बैच का अनिवार्य परीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमूल की डेयरियां और एनडीडीबी की संस्थाओं से जुड़े किसानों को भी आर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि किसानों को उनके ऑर्गेनिक उत्पादों के बदले उचित मूल्य मिलना चाहिए ताकि वे ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रेरित हो सकें। श्री शाह ने NCOL और सहकारिता मंत्रालय को कहा कि अमूल के साथ Bharat Organics पर एक बैठक करके ऑर्गेनिक आटे, और ऑर्गेनिक अरहर दाल के दामों को इस प्रकार से निश्चित करना चाहिए जिससे किसानों को फायदा पहुंचे और वे ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज्यादा प्रेरित हों। श्री शाह ने कहा कि एक बार अगर किसान को ज्यादा दाम मिलने की शुरुआत होगी तो निश्चित ही किसान धीरे-धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रोत्साहित होंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अगर मार्केटिंग अच्छी होगी, तो जिस प्रकार से ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति लोगों में जागरूकता है, उससे निश्चित रूप से पूरे देश में इन उत्पादों की मांग कई गुना बढ़ेगी। उन्होंने आगामी पर्व-त्योहारों में ऑर्गेनिक उत्पादो को और बढ़ावा देने की अपील की।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश के सभी PACS कृषि उत्पाद के स्रोत, ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के केन्द्र, और बीजों की बिक्री के केन्द्र बनें ताकि NCOL, NCEL और BBSSL जैसी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को भी बढ़ावा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि इन 2 लाख सहकारी समितियों में कम से कम एक ऐसे युवा किसान को जोड़ना चाहिए जो आगे चलकर स्थानीय सहकारी ढांचे को मजबूत बनाने में प्रेरक का काम कर सके। श्री शाह ने PACS के सदस्यों के साथ-साथ किसानों के समुचित प्रशिक्षण पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि नाबार्ड को सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर नये PACS ऐसी कार्यप्रणाली निर्धारित करनी चाहिए जिससे प्रत्येक किसान को उसके क्षमता के अनुरूप ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

किसानों को उपार्जित मूल्य की राशि समय पर मिले : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 23 जनवरी तक होगी 36 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन पूर्ण

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में हो रहे धान उपार्जन कार्य की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को समय पर उपार्जित धान की राशि प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में एक बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा एवं प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी से धान उपार्जन के संबंध में चर्चा की।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक साढ़े पांच लाख किसानों से अधिक किसानों से 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी जिलों में उपार्जन केन्द्रों पर संपन्न हो चुकी है। प्रदेश में लगभग 44 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है। प्रदेश में धान का उपार्जन 23 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है। किसानों के खाते में 5 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से कृषि क्षेत्र में नई क्रांति

बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि- 2024-25 के दौरान 122528.77 करोड़ रुपये की राशि

पीएम-किसान-पीएम-किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

2023-24 में धान (सामान्य) के लिए एमएसपी रु. 2,300 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि गेहूं के लिए एमएसपी बढ़ाकर रु. 2,425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत रु. 1.70 लाख करोड़ से अधिक दावों का भुगतान किया गया है और

कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण- कृषि में जमीनी स्तर पर ऋण वितरण में 349 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में रु. 7.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2021-22 में रु. 1,425 हो गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में रु. 25.48 लाख करोड़

डिजिटल कृषि मिशन, 02.09.2024 को रु. 2,817 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत

23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1410 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया

खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ यह 2024

नईदिल्ली। कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय फसल विविधीकरण और गुणात्मक इनपुट तथा कृषि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के संदर्भ में उत्पादन पहलुओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के कल्याण के लिए डीएएंडएफडब्ल्यू की प्रमुख

उपलब्धियां:

1. **बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि-** 2024-25 के दौरान किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत 122528.77 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
2. **रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन-** तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन 332.30 मिलियन टन दर्ज किया गया है, जबकि बागवानी उत्पादन 352.23 मिलियन टन है।
3. **पीएम-किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता-** पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण -डीबीटी के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन बराबर किस्तों में 6,000 रूपये प्रति वर्ष हस्तांतरित किए जाते हैं। यह योजना तकनीकी और प्रक्रिया प्रगति का लाभ उठाती है ताकि अधिकतम लाभार्थी बिना किसी परेशानी के लाभान्वित हो सकें। पीएम-किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। 18 किस्तों के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थी किसानों को कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया है।
4. **कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)-** रु.1 लाख करोड़ के आवंटन के साथ शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कटाई के बाद के प्रबंधन और सामुदायिक खेती के बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करना है। यह 7 वर्षों तक के लिए रु.2 करोड़ तक के ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सहायता और सीजीटीएमएसई योजना के माध्यम से रु.2 करोड़ तक के ऋण के लिए ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करता है। 2020 में अपनी स्थापना के बाद से, एआईएफ ने 84,159 परियोजनाओं के लिए रु.51,364 करोड़ मंजूर किए हैं। इनमें गोदाम, प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड स्टोरेज और अन्य कटाई के बाद की सुविधाएं शामिल हैं। 28.08.2024 को सरकार ने सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को एकीकृत करने, द्वितीयक प्रसंस्करण और पीएम-कुसुम घटक-ए के साथ अभिसरण सहित एआईएफ के दायरे का विस्तार करने के उपायों को मंजूरी दी। इन पहलों का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, इनपुट लागत को कम करना, उत्पादकता मंम सुधार करना और कृषि आय में वृद्धि करना है। जिससे भारत में सतत कृषि विकास का समर्थन हो सके।
5. **एफपीओएस को बढ़ावा-** 29 फरवरी 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई, 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का बजट 2027-28 तक रु.6,865 करोड़ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाबार्ड, एसएफएसी, नेफेड और अन्य सहित 14 एजेंसियों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की देखरेख करता है। आवंटित 10,000 एफपीओ में से 9,180 पंजीकृत हो चुके हैं।
6. **उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी तय करना-** सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है। 2023-24 में धान (सामान्य) के लिए एमएसपी रु.2,300 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि गेहूं के लिए एमएसपी बढ़ाकर रु.2,425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
7. **नमो ड्रोन दीदी योजना-** सरकार ने किसानों को उर्वरक और कीटनाशक लगाने जैसी किराये की सेवाएं देने के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए 1,261 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। 2023-24 में, 500 ड्रोन खरीदे गए (स्वयं के संसाधनों से) और लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) द्वारा वितरित किए गए। शेष 14,500 ड्रोन 2024-25 और 2025-26 में प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य स्थायी व्यावसायिक अवसर प्रदान करना है, जिसमें एसएचजी को सालाना कम से कम 1 लाख रुपये की कमाई हो।
8. **प्रति बूंद अधिक फसल-** 2015-16 में शुरू की गई प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। शुरुआत में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत लागू किया गया, यह अब 2022-23 से आरकेवीवाई का हिस्सा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत और अन्य को 45 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2015-16 से 2024-25 (दिसंबर 2024) तक लगभग 95 लाख हेक्टेयर को कवर किया गया है। 2020-21 में नीति आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन में पाया गया कि पीडीएमसी जल उपयोग दक्षता (30 से 70 प्रतिशत) में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि (10 से 69 प्रतिशत) और रोजगार के अवसर सृजित करने में प्रभावी है।
9. **कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण-** कृषि में जमीनी स्तर पर ऋण वितरण में 349 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में रु.7.30 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में रु.25.48 लाख करोड़ हो गया है। इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के ऋण शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, अल्पकालिक ऋणों में भी 275 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यह वित्त वर्ष 2013-14 में रु.5.48 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में रु.15.07 लाख करोड़ हो गया है। यह पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से अल्पकालिक ऋण निवेश 270 प्रतिशत बढ़कर रु.3.63 लाख करोड़ से रु.9.81 लाख करोड़ हो गया है।
10. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) -** 2016 में शुरू]पीएमएफबीवाई प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं के कारण फसल के नुकसान पर व्यापक कवरेज प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत रु.1.70 लाख करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। कृषि रक्षक पोर्टल (केआरपीएच) और एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन (14447) कुशल शिकायत निवारण के लिए स्थापित की गई है। इससे किसान शिकायतों को ट्रैक कर सकते हैं और एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित कर सकते हैं।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सहकारिता मंत्रालय 2024 : विकास, नवाचार और समृद्धि की ओर बढ़ते कदम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के "सहकार से समृद्धि" के सपने को मूर्त रूप देने के लिए 6 जुलाई, 2021 को एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और जीवंत बनाने के लिए विभिन्न पहलों और ऐतिहासिक कदमों को उठाया है। पिछले तीन वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने 56 प्रमुख पहलों को कार्यान्वित किया है, जिससे देश भर में सहकारी समितियों के आर्थिक विकास और विस्तार के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। इन पहलों पर अब तक हुई प्रगति और विवरण इस प्रकार हैं:

• आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने 130 वर्षों में पहली बार आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता समिति वर्ष 2025 का भी शुभारंभ किया और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

• अरहर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए पोर्टल

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 4 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में अरहर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड (एनएएफईडी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन लिमिटेड (एनसीसीएफ) द्वारा विकसित पोर्टल का शुभारंभ किया।

• आरसीएस और एआरडीबी के कार्यालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण योजना

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कार्यालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण योजना का शुभारंभ किया।

• सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) में 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 24 फरवरी 2024 को गोदामों और अन्य कृषि-संबंधी अवसंरचना के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पीएसीएस की आधारशिला रखी और 18,000 पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना का भी उद्घाटन किया।

• शहरी सहकारी बैंकों के लिए छतरी संगठन

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 2 मार्च 2024 को नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए छतरी संगठन, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन किया।

• एनसीओएल और यूओसीबी के बीच समझौता ज्ञापन

राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और उत्तराखंड आर्गेनिक्स कमोडिटी बोर्ड (यूओसीबी) के बीच 30 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

• 10,000 एमपीएसीएस, डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियों का शुभारंभ

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियों के साथ-साथ 10,000 नव स्थापित बहु-उद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (एमपीएसीएस) का उद्घाटन किया।

(ए) प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण

1. पीएसीएस को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उप-नियम

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय फेडरेशनों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद पीएसीएस के लिए आदर्श उप-नियम तैयार किए गए और 5 जनवरी 2023 को इसे जारी कर दिया गया।

• इन आदर्श उप-नियमों का उद्देश्य पीएसीएस/एलएएमपीएस की आय के स्रोतों को बढ़ाना और डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण आदि जैसे 25 से अधिक नए क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। अब तक, 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आदर्श उप-नियमों को अपना लिया है या उनके मौजूदा उप-नियम इस आदर्श उप-नियमों के अनुरूप हैं।

2. कम्प्यूटरीकरण के जरिए पीएसीएस को सुदृढ़ करना

• पीएसीएस/एलएएमपीएस का कम्प्यूटरीकरण वित्त वर्ष 2024-25 में जारी रहा तथा क्रियाशील पीएसीएस/एलएएमपीएस को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के जरिए नाबार्ड से जोड़ा गया।

• अब तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 67,930 पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इस काम के लिए केंद्र सरकार द्वारा हार्डवेयर खरीद, डिजिटलीकरण तथा सहायक प्रणालियों की स्थापना के लिए राज्यों को कुल 700.42 करोड़ रुपए तथा नाबार्ड को 165.92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18,000 पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना का उद्घाटन किया।

3. प्रत्येक पंचायत/गांव में बहु-उद्देशीय पीएसीएस/डेयरी/मछली पालन सहकारी समितियों की स्थापना

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी, 2023 को इस योजना को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश की सभी पंचायतों/गांवों को शामिल करते हुए नई बहु-उद्देशीय पीएसीएस, डेयरी, मछली पालन सहकारी समितियों की स्थापना करना है।

• यह योजना नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्य सरकारों के सहयोग से इन प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करके लागू की जा रही है।

• योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 19 सितम्बर, 2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) भी शुरू की गई, जिसमें लक्ष्य, समयसीमा और संबंधित हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 10,825 नई एम-पीएसीएस, डेयरी और मछली पालन संबंधी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी, जिसे 31 मई, 2023 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से पीएसीएस स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे, जैसे गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानें आदि का निर्माण करना शामिल है।

• केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने, खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और पीएसीएस स्तर पर ही विभिन्न कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए इस परियोजना पर विशेष बल दे रहे हैं।

• पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों के 11 पीएसीएस में गोदामों का उद्घाटन किया गया और 500 अतिरिक्त पीएसीएस में गोदाम निर्माण की आधारशिला 24 फरवरी, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई।

5. ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पीएसीएस

• सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच 2 फरवरी,2023को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि पीएसीएस को सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। सीएससी-एसपीवी और नाबार्ड के समन्वय में एनसीसीटी द्वारा इन पीएसीएस को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

• अब तक 41,075 पीएसीएस ने सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है और इन पीएसीएस के जरिए 60 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 21 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में इस परियोजना का उद्घाटन किया। देश के सभी क्रियाशील पीएसीएस/एलएएमपीएस के माध्यम से सीएससी सुविधाएं प्रदान करने की योजना है, जिन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

6. पीएसीएस द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन

• एफपीओ योजना के तहत सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को 1100 अतिरिक्त एफपीओ आवंटित किए गए हैं। अब पीएसीएस, एफपीओ के रूप में, कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक गतिविधियां कर सकेंगे। यह पहल सहकारी समितियों के सदस्यों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक बाजार संपर्क उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी।

एलपीजी वितरक के लिए पीएसीएस की पात्रता

• सहकारिता मंत्रालय पीएसीएस की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। पीएसीएस को एलपीजी वितरक के लिए पात्र बनाना इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएसीएस को एलपीजी वितरक के लिए पात्र बनाने हेतु अपने नियमों में संशोधन किया है।

(शेष अगले अंक में)

गांधी शिल्प बाजार का भव्य शुभारंभ इंदौर में

इंदौर: किला मैदान स्थित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा आयोजित "गांधी शिल्प बाजार" का भव्य शुभारंभ विधानसभा क्षेत्र क्र. 3, इंदौर के लोकप्रिय माननीय विधायक श्री राकेश गोलू जी शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्रीमती अर्पणा देशमुख (सहायक निदेशक, हस्तशिल्प विकास आयुक्त), सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट, म.प्र. राज्य सहकारी संघ की विशेषज्ञ संस्था से श्री धर्मेंद्र सिंह राजपूत, श्रीमती राधा शर्मा, श्री सुयश शर्मा, श्री राहुल श्रीवास, श्री प्रदीप कुमार रैकवार, एवं समस्त शिल्पकार और कर्मचारी उपस्थित रहे।

विधायक श्री राकेश गोलू जी शुक्ला ने शिल्पकारों को संबोधित करते हुए कहा कि "हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं, बल्कि इनकी कला और शिल्प की अद्वितीयता देश और दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिलाती है। इस बाजार में प्रदर्शित कलाकृतियों के माध्यम से हम अपने कारीगरों और कलाकारों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि इस आयोजन के द्वारा हम इन शिल्पकारों को उत्साहवर्धन देने में सफल हो रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा, "इस तरह के आयोजनों से न केवल स्थानीय शिल्पकारों का हौसला बढ़ता है, बल्कि यह हमारे कारीगरों की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस आयोजन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों को बधाई देता हूं।"

श्रीमती अर्पणा देशमुख, सहायक निदेशक, हस्तशिल्प विकास आयुक्त ने इस अवसर पर कहा, "हस्तशिल्प कारीगरी हमारे समाज की एक अमूल्य धरोहर है, जिसे संजोकर रखना और उसका सही तरीके से प्रचार-प्रसार करना हमारी जिम्मेदारी है। गांधी शिल्प बाजार जैसी पहल शिल्पकारों को उनके अद्भुत कार्यों को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करती है। इससे न केवल शिल्पकारों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता को देशभर में पहचान मिलती है। मैं इस आयोजन में शामिल सभी शिल्पकारों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि यह बाजार और इस तरह के आयोजन भविष्य में शिल्पकारों को और अधिक अवसर प्रदान करेंगे।"

शिल्प बाजार में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों और कलाकारों ने अपने द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। विधायक महोदय ने इन शिल्पकारों से संवाद करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की और उन्हें उत्साहित किया।

मध्यप्रदेश को प्राकृतिक खेती में अग्रणी बनाने उत्पादों की करें ब्रांडिंग

प्राकृतिक खेती के संवर्धन पर मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग ने किया संवाद

भोपाल : मध्यप्रदेश को प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनाने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाना चाहिए। महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर कम्युनिटी मॉडल अपनाए जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती के लिए मानकों और प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। उक्त विचार विशेषज्ञों ने आज यहां मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा "जलवायु सहनशीलता और सतत् कृषि के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: मार्ग, चुनौतियां और नीति समर्थन" विषय पर आयोजित संवाद में व्यक्त किए। संवाद में कृषि, बागवानी और सतत विकास के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, महिला किसानों, स्वयंसेवी संगठनों, और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

सीईओ, राज्य नीति आयोग श्री ऋषि गर्ग ने प्राकृतिक खेती के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने में किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। आंध्रप्रदेश के उप निदेशक हॉर्टिकल्चर श्रीनिवासुलु ने सामुदायिक प्राकृतिक खेती के अनुभव साझा करते हुए कहा कि कम लागत और स्थानीय संसाधनों का उपयोग प्राकृतिक खेती को किसानों के लिए आकर्षक बनाता है।

अतिरिक्त सचिव बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती प्रीति मैथिल ने बताया कि प्राकृतिक खेती के उत्पाद उपभोक्ताओं में लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए बेहतर नीति समर्थन और बाजार संपर्क की आवश्यकता है। श्री जी. प्रकाश राव ने प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक आधार, जैव विविधता में सुधार और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।

पद्मश्री डॉ. सुभाष पालेकर ने जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और प्राकृतिक खेती को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के सुझाव दिए। उन्होंने "शून्य लागत प्राकृतिक खेती" की तकनीकों पर जोर दिया। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने विशेषज्ञों से संवाद किया।

अपेक्स बैंक के शाखा प्रबंधकों की बैठक भोपाल में समन्वय भवन में सम्पन्न

भोपाल: अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सभी शाखा प्रबंधकों की बैठक समन्वय भवन में आयोजित की गई। बैठक में बैंक के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

बैठक में श्रीमती अरुणा दुबे, वि.क.अ. ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य शाखा प्रबंधकों का उत्साहवर्धन करना है और उन्हें अपनी समस्याएं साझा करने के लिए प्रेरित किया गया।

श्रीमती कृति सक्सेना, वि.क.अ. ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना पर विस्तार से चर्चा की और शाखा प्रबंधकों से इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ ग्राहकों तक पहुँचाने की अपील की।

बैंक के उप महाप्रबंधक श्री आर.एस. चंदेल ने शाखाओं की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया और एसएलबीसी के निर्देशों के अनुसार बैंकिंग सुविधाओं को प्रात: 10 बजे से सांय 4 बजे तक निरंतर उपलब्ध कराने की बात कही।

श्री के.टी.सज्जन ने शाखाओं में प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यवसाय संवर्धन के लिए व्यक्तिगत ऋण वितरण पर जोर दिया और इसे बेहतर माध्यम बताया।

बैठक में बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज कुमार गुप्ता द्वारा 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक विशेष सावधि जमा (एफ.डी.) पर विशेष ब्याज दर 7.60% और 7.10% देने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज देने की सुविधा भी जारी रहेगी।

बैठक का संचालन श्री करुण यादव, प्रबंधक ने किया, और इसमें श्री अजय देवड़ा, श्री सुशील कुशवाह सहित सभी संभागीय एवं अमानत शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित हुए।

दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुना करने के लिए राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम, एनडीडीबी के साथ सहकारिता अनुबंध पर कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर और मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। देश के दुग्ध उत्पादन में 57.62% की वृद्धि हुई है और यह विश्व रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का औसत 673 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि राष्ट्रीय औसत 471 ग्राम से अधिक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के अनुसार ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुना करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच सहकार्यता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) किया गया है। इसे मंत्रि-परिषद ने भी मंजूरी दे दी है। अनुबंध की अवधि 5 वर्ष होगी, जिसका आपसी सहमति से विस्तार किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि अनुबंध के तहत मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे, दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी तथा दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की जायेगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि

इस सबके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ रूपये से बढ़कर दोगुना से भी अधिक (3500 करोड़ रूपये) हो जाएगी। मध्यप्रदेश देश का डेयरी कैपिटल बन जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेयरी सहकारी समिति एवं कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत ढाई हजार करोड़ रूपये के निवेश से प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट एवं चिलिंग सेंटर की संख्या में वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संकल्पों को पूरा करने में एनडीडीबी के साथ हुआ अनुबंध महत्वपूर्ण साबित होगा। यह राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्रांड को मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार है, जिसे बढ़ाकर 9 हजार किया जाएगा। एक दुग्ध समिति लगभग 1 से 3 गांव में दुग्ध संकलन करती है, 9 हजार दुग्ध समितियां के माध्यम से लगभग 18 हजार ग्रामों को कवर किया जा सकेगा। दुग्ध संकलन भी 10.50 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एनडीडीबी द्वारा दुग्ध उत्पादक संस्थाओं (एमपीओ) के माध्यम से कवर किए गए गांव की संख्या 1390 से बढ़ाकर 2590 की जाएगी तथा दूध की खरीद को 1.3 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 3.7 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वर्तमान में डेयरी प्लांट की क्षमता 18 लाख किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 30 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा।

सांची ब्रांड होगा और मजबूत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के सांची ब्रांड को और मजबूत किया जाएगा। व्यापक प्रचार-प्रसार से इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जायेगा। ब्रांड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दुग्ध संघ के प्रबंधन एवं संचालन के लिए प्रबंधन शुल्क और नए प्र-संस्करण प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आवश्यकता अनुसार तकनीकी एवं प्रबंधन विशेषज्ञों को सरकार के पे-रोल पर दुग्ध संघ में पदस्थ किया जाएगा तथा कार्यरत अमले का हित संरक्षण भी किया जाएगा। दुग्ध सहकारी समितियां से संबद्ध डेयरी किसानों की शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी।

दुग्ध उत्पादकों की समृद्धि के लिए समर्पित सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि विगत चैत्र माह से प्रारंभ हुए नव वर्ष से आने वाली गुड़ी-पड़वा तक गौ-वंश रक्षा वर्ष मनाया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने प्रदेश के हर ब्लॉक में एक गाँव को वृंदावन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सरकार ने दुधारू पशु पालने पर अनुदान तथा दुग्ध उत्पादन पर बोनस देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पशुपालकों एवं गौ-संवर्धन के लिए पूरी तरह समर्पित है।

(पृष्ठ 2 का शेष)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से .....

11. ई-नाम प्लेटफॉर्म की स्थापना- विभाग ने 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1410 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया है। 31.12.2024 तक 1.78 करोड़ किसान और 2.63 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। कुल 11.02 करोड़ मीट्रिक टन और 42.89 करोड़ नंबर (बांस, सुपारी, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से लगभग 4.01 लाख करोड़ रुपये का व्यापार ई-नाम प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया है।

12. डिजिटल कृषि मिशन- केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के विकास की घोषणा की, जिसे 2024-25 के बजट में और बढ़ाया गया। डीपीआई किसानों पर व्यापक डेटा प्रदान करेगा। इसमें जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलें शामिल हैं। यह अभिनव, किसान-केंद्रित सेवाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार के डेटा को एकीकृत करती हैं। 02.09.2024 को रु.2,817 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत डिजिटल कृषि मिशन पहल के मूल में तीन प्रमुख डीपीआईशामिल हैं: एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस), और मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्रण। एग्रीस्टैक 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल आईडी बनाएगा और एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करेगा। डीएसएस फसलों, मिट्टी, मौसम और पानी पर भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत करेगा, जबकि मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्र 142 मिलियन हेक्टेयर को कवर करेगा। मिशन में सटीक उपज अनुमानों के लिए डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य 2,50,000 प्रशिक्षित युवाओं और कृषि सखियों के लिए रोजगार सृजित करना तथा एआई और रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किसानों को सेवा प्रदान करना है।

13. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना- 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) कार्यक्रम राज्य सरकारों को किसानों को एसएचसी जारी करने में सहायता करते हैं। 2022-23 से, उन्हें आरकेवीवाई के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता घटक के अंतर्गत मिला दिया गया। 2024-25 की उपलब्धियों में शामिल हैं:

- 75 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए, 92 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 53 लाख एसएचसी बनाए गए।
- आबंटित 201.85 करोड़ रुपये में से 109.87 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- 1,020 स्कूलों में स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, 1,000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं और 125,972 छात्रों का नामांकन हुआ है।
- 31 लाख किसानों को एटीएमए से मृदा स्वास्थ्य सलाह मिली।

14. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में देश भर में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) शुरू किया है। इस योजना का कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपये है।

15. आरकेवीवाई के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक- आरकेवीवाई के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक, जो मूल रूप से 2016-17 से 2021-22 तक कृषि वानिकी पर उप-मिशन (एसएमएएफ) का हिस्सा है। यह अतिरिक्त किसान आय के लिए खेत पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है। इस अवधि में 1.21 लाख हेक्टेयर में 532.298 लाख पेड़ लगाए गए और 899 नर्सरी स्थापित की गई। इससे लगभग 1.86 लाख किसान लाभान्वित हुए। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री प्रदान करने और विभिन्न हितधारकों द्वारा नर्सरी की स्थापना का समर्थन करने के लिए 2023-24 में योजना का पुनर्गठन किया गया। 2023-24 में, 162 नई कृषि वानिकी नर्सरियों के लिए रु.58.10 करोड़ जारी किए गए और 470 मौजूदा नर्सरियों ने पौधे उगाना शुरू कर दिया। 2024-25 में 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 33.24 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें दिसंबर 2023 में नर्सरियों के लिए मान्यता प्रोटोकॉल विकसित किए गए। अब तक 133 नर्सरियों को मान्यता दी जा चुकी है।

16. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)- आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) का उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और 'मीठी क्रांति' हासिल करना है। 2020-23 के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ, इस योजना को 370 करोड़ रुपये शेष रहते हुए 2025 तक बढ़ा दिया गया था। यह एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी), शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं, मधुमक्खी पालन उपकरण निर्माण इकाइयां और कस्टम हायरिंग केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए तीन मिनी मिशनों (एमएम-I, एमएम-II, एमएम-III) पर केंद्रित है। प्रमुख उपलब्धियों में 8 क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं, 33 शहद प्रसंस्करण इकाइयां, 1305 हेक्टेयर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, 385 हेक्टेयर मधुमक्खी-अनुकूल वृक्षारोपण शामिल हैं।

17. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) - 2014-15 से 2024-25 तक, एमआईडीएच के अंतर्गत एनएचएम/एचएमएनईएच योजना ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है: 13.96 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलों का विस्तार किया गया, 908 नर्सरियां स्थापित की गईं; 1.52 लाख हेक्टेयर पुराने बागों का कायाकल्प किया गया और 52,459 हेक्टेयर जैविक खेती के अंतर्गत कवर किया गया। इसके अतिरिक्त, 3.08 लाख हेक्टेयर संरक्षित खेती के अंतर्गत कवर किए गए, 55,347 जल-संचयन संरचनाएं बनाई गईं और 16.45 लाख मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया। इसके अलावा, 9.77 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया। योजना में हाल के बदलावों में राष्ट्रव्यापी कवरेज, मखाना और औषधीय फसलों को शामिल करना, और एफआरए पट्टा भूमि और लाख कीट मेजबान पौधों के बागानों वाले आदिवासी परिवारों को लाभ प्रदान करना शामिल है।

18. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - तिलहन (एनएमईओ-तिलहन)- खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - तिलहन (एनएमईओ-तिलहन) का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह 2024-25 से 2030-31 तक चलेगा। मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना है। इस पहल से उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों, चावल की परती खेती और अंतर-फसल को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल की 72 प्रतिशत ज़रूरतों को पूरा करना है।

19. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना: 2014-15 में शुरू की गई कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) कृषि मशीनरी खरीदने और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), हाई-टेक हब और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उपलब्धियाँ (2014-15 से 2024-25, नवंबर 2024 तक):

- राज्यों में 8,565 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- ट्रैक्टर और पावर टिलर सहित 1,909,809 कृषि मशीनें वितरित की गईं।
- 26,637 सीएचसी, 609 हाई-टेक हब और 24,176 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए।
- किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 141.39 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें आईसीएआर को 296 ड्रोन खरीदने के लिए 52.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- किसानों को 527 ड्रोन दिए गए और 1,595 ड्रोन सीएचसी स्थापित किए गए।
- आईसीएआर ने 287 कर्मियों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया है।
- 30,234.7 हेक्टेयर क्षेत्र में 27,099 ड्रोन प्रदर्शन किए गए, जिससे 351,856 किसान लाभान्वित हुए।

20. 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना (नवंबर, 2024 तक): 2018-19 में शुरू की गई फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना, वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी पर सब्सिडी देने में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सहायता करती है।

उपलब्धियाँ:

- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आईसीएआर को 4,391.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- 319,103 इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें वितरित की गईं।
- 40,996 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए।
- 2023 की तुलना में 2024 के मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने की घटनाओं में 57 प्रतिशत की कमी आई है।

21. जलवायु लचीली किस्में- बाढ़/जल डूब/जल भराव सहनशीलता, सूखा/नमी तनाव/जल तनाव सहनशीलता, लवणता/क्षारीयता/सोडियम मिट्टी सहनशीलता, ताप तनाव/उच्च तापमान सहनशीलता, ठंड/ठंढ/सर्दियों में ठंड सहनशीलता सहित चरम जलवायु के लिए विशेष रूप से अनाज, तिलहन, दलहन, चारा फसलों, फाइबर फसलों और शर्करा फसलों की जलवायु लचीली फसल किस्मों को सटीक फेनोटाइपिंग उपकरणों का उपयोग करके विकसित किया गया है। आईसीएआर ने हाल ही में 109 जलवायु लचीली किस्में जारी की हैं जो किसानों को कृषि जलवायु परिस्थितियों के आधार पर इसे अपनाने में मदद करेंगी।

22. विस्तार सुधार (एटीएमए) योजना

एटीएमए, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्तमान में देश के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 739 जिलों में लागू किया जा रहा है। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत और किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। योजना का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करना और विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करना और फार्म स्कूल आदि के माध्यम से किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीक और अच्छी कृषि पद्धतियाँ उपलब्ध कराना है।

सरकार के सभी प्रयास और पहल कृषक समुदाय को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं।

एफपीओ एवं सीबीबीओ का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में एफपीओ (Farmer Producer Organization) एवं सीबीबीओ (Cluster Based Business Organization) विषय पर एक दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एफपीओ की अवधारणा, उद्देश्यों और लाभों की जानकारी प्रदान करना, सीबीबीओ के रूप में सहकारी संघ की भूमिका स्पष्ट करना, बेसलाइन सर्वे और मोबिलाइजेशन प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालना और एफपीओ के गठन एवं संचालन में सहकारी संघ की भूमिका को सुदृढ़ बनाना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह ने किया। उन्होंने एफपीओ गठन के महत्व और सीबीबीओ के रूप में सहकारी संघ की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

एफपीओ की अवधारणा और उद्देश्य:

श्री योगेश द्विवेदी, सीईओ, मध्यभारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ने एफपीओ के लाभ और किसानों की सामूहिक शक्ति को बढ़ाने में उनके महत्व पर चर्चा की।

बेसलाइन सर्वे और मोबिलाइजेशन प्रक्रिया:

श्री द्विवेदी ने बेसलाइन सर्वेक्षण की प्रक्रिया, डेटा संग्रह, समस्या विश्लेषण और समाधान की पहचान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया। उन्होंने गाँव में मोबिलाइजेशन और किसानों को एफपीओ में शामिल करने की रणनीतियों पर भी जोर दिया।

सीबीबीओ की भूमिका:

श्री गौरव जादौन, एनसीडीसी भोपाल, ने एफपीओ गठन में सीबीबीओ की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक सहायता के महत्व को रेखांकित किया।

कानूनी आवश्यकताएँ और संचालन:

श्री संजय कुमार सिंह और श्री राहुल कुशवाहा, एनसीडीसी भोपाल, ने एफपीओ के पंजीकरण, कानूनी ढांचे, व्यावसायिक योजनाओं और नवाचार के माध्यम से उत्पाद विकास पर जानकारी साझा की।

सहकारिता से बनने वाले एफपीओ: योजना और लाभ

एफपीओ किसानों को सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। सहकारिता आधारित एफपीओ न केवल उत्पादन और भंडारण में मदद करता है, बल्कि विपणन और मूल्यवर्धन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सहकारी संघ की भूमिका:

- **तकनीकी सहायता :** आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षण का प्रावधान।
- **वित्तीय सहयोग :** सहकारी ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ।
- **प्रशिक्षण और मोबिलाइजेशन:** किसानों को एफपीओ की उपयोगिता समझाना।

सरकारी योजनाएँ:

1. **प्रधानमंत्री एफएमई योजना:** कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता।
2. **एनसीडीसी योजनाएँ:** एफपीओ को वित्तीय सहायता।
3. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन और भंडारण के लिए अनुदान।

कार्यक्रम में सहकारी संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने एफपीओ गठन और संचालन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा की।कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। श्री संजय कुमार सिंह ने सभी विशेषज्ञों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

एक जिला-एक औषधीय उत्पाद" की शुरुआत चयनित 5 जिलों से करें: आयुष मंत्री श्री परमार

"धरती आबा अभियान" अंतर्गत पोषण वाटिका एवं औषधीय उद्यान (हर्बल गार्डन) विकसित करने की बनाएं कार्य योजना

आयुष मंत्री की अध्यक्षता में मप्र राज्य औषधीय पादप बोर्ड की बैठक हुई

भोपाल :उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने देवारण्य योजना 2.0 के अंतर्गत "एक जिला-एक औषधीय उत्पाद" योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 5 जिलों का चयन कर, समग्र कार्य योजना बनाकर आवश्यक क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मंत्री श्री परमार मंत्रालय में म.प्र. राज्य औषधीय पादप बोर्ड के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मंत्री श्री परमार ने बोर्ड के कार्यों की प्रगति एवं आगामी कार्य योजना की गहन समीक्षा कर, विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने प्रदेश का औषधीय मैप तैयार करने एवं अन्य फसलों की तरह समस्त औषधीय फसलों को फसल गिरदावरी में सम्मिलित कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने को भी कहा। मंत्री श्री परमार ने औषधीय पौधों की एम.एस.पी. के निर्धारण के लिए वन विभाग, मनरेगा, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग तैयार कर समन्वय कर व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री परमार ने "धरती आबा अभियान" में पोषण वाटिका एवं रेसिडेंशियल स्कूलों में भी औषधीय उद्यान के विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने आयुष विभाग अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में औषधीय उद्यान (हर्बल गार्डन) विकसित करने को भी कहा। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव आयुष श्री डी.पी. आहूजा, आयुक्त आयुष श्रीमति उमा आर. माहेश्वरी और अपर सचिव आयुष एवं बोर्ड के सीईओ श्री संजय कुमार मिश्र सहित विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे।

कैलेण्डर वर्ष-2025

जनवरी 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

फरवरी 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

मार्च 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

अप्रैल 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

मई 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

जून 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

जुलाई 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

अगस्त 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

सितम्बर 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

अक्टूबर 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

नवम्बर 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

दिसम्बर 2025

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

शासकीय अवकाश- समस्त रविवार

26 जनवरी - गणतंत्र दिवस, 12 फरवरी - *संत रविदास जयन्ती, 26 फरवरी - महाशिवरात्रि, 14 मार्च - होली, 30 मार्च - गुड़ी पड़वा/ महर्षि गौतम जयन्ती/ चैती चांद, 31 मार्च - ईद-उल-फित्र, 1 अप्रैल - †बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी, 6 अप्रैल - रामनवमी, 10 अप्रैल - महावीर जयन्ती, 14 अप्रैल - *डॉ. अम्बेडकर जयन्ती/वैशाखी, 18 अप्रैल - पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे), 30 अप्रैल - *परशुराम जयन्ती, 12 मई - बुद्ध पूर्णिमा, 29 मई - *महाराणा प्रताप जयन्ती/ छत्रसाल जयन्ती, 7 जून - ईदुज्जुहा, 6 जुलाई - मोहर्रम, 9 अगस्त - रक्षाबंधन, 15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त - जन्माष्टमी, 5 सितम्बर - मिलाद-उन-नबी, 2 अक्टूबर - गाँधी जयन्ती/दशहरा (विजयादशमी), 7 अक्टूबर - *महर्षि वाल्मीकी जयन्ती, 20 अक्टूबर - दीपावली, 21 अक्टूबर - गोवर्धन पूजा, 5 नवम्बर - गुरुनानक जयन्ती, 15 नवम्बर - *राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस (भगवान बिरसा मुण्डा जयन्ती), 25 दिसम्बर - ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस), * कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिए यह छुट्टियाँ नहीं हैं. † केवल कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिए यह छुट्टी है.

ऐच्छिक (आप्शनल) छुट्टियाँ- (1) 1 जनवरी-नववर्ष दिवस, (2) 6 जनवरी-महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस/गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस, (3) 14 जनवरी-मकर संक्रांति/पोंगल, (4) 21 जनवरी-हेमू कालाणी का शहीदी दिवस, (5) 3 फरवरी-बसंत पंचमी, (6) 4 फरवरी-देव नारायण जयन्ती/नर्मदा जयन्ती, (7) 11 फरवरी-स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस, (8) 14 फरवरी-शब-ए-बारात, (9) 19 फरवरी-छत्रपति शिवाजी जयन्ती, (10) 20 फरवरी-शबरी जयन्ती, (11) 26 फरवरी-एकलव्य जयन्ती, (12) 13 मार्च-होली (होलिका दहन), (13) 18 मार्च-टोडरमल जयन्ती, (14) 20 मार्च-वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस, (15) 25 मार्च-भक्त माता कर्मा जयन्ती, (16) 28 मार्च-जमात-उल-विदा, (17) 31 मार्च-भगवान मीनेष जयन्ती, (18) 2 अप्रैल-निषादराज जयन्ती, (19) 11 अप्रैल-महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती/हाटकेश्वर जयन्ती, (20) 14 अप्रैल-विशु, (21) 24 अप्रैल-वल्लभाचार्य जयन्ती, (22) 25 अप्रैल-सेन जयन्ती, (23) 30 अप्रैल-अक्षय तृतीया, (24) 2 मई-शंकराचार्य जयन्ती (एकात्मता दिवस/दार्शनिक दिवस), (25) 15 मई-केवट जयन्ती, (26) 31 मई-माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस, (27) 4 जून-महेश जयन्ती, (28) 6 जून-ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस), (29) 9 जून-बड़ा महादेव पूजन, (30) 11 जून-कबीर जयन्ती, (31) 14 जून-गदीर-ए-खुम, (32) 24 जून-वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस, (33) 27 जून-रथ यात्रा, (34) 5 जुलाई-योम-ए-अशुरा, (35) 10 जुलाई-गुरु पूर्णिमा, (36) 29 जुलाई-नागपंचमी, (37) 31 जुलाई-गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती, (38) 9 अगस्त-जनजातीय दिवस, (39) 13 अगस्त-दुर्गादास राठौर जयन्ती, (40) 14 अगस्त-बलराम जयन्ती, (41) 15 अगस्त-पारसी नववर्ष दिवस, (42) 27 अगस्त-गणेश चतुर्थी, (43) 30 अगस्त-नवाखाई, (44) 2 सितम्बर-तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी, (45) 3 सितम्बर-डोल ग्यारस, (46) 5 सितम्बर-ओणम, (47) 6 सितम्बर-अनंत चतुर्दशी, (48) 17 सितम्बर-विश्वकर्मा जयन्ती, (49) 18 सितम्बर-राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस, (50) 20 सितम्बर-प्राणनाथ जयन्ती, (51) 22 सितम्बर-अग्रसेन जयन्ती, (52) 30 सितम्बर-दशहरा (महाष्टमी), (53) 1 अक्टूबर-दशहरा (महानवमी), (54) 7 अक्टूबर-महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव, (55) 10 अक्टूबर-करवाचौथ पर्व, (56) 21 अक्टूबर-दीपावली का दूसरा दिन, (57) 23 अक्टूबर-भाईदूज (58) 27 अक्टूबर-छठ पूजा, (59) 28 अक्टूबर-भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती, (60) 1 नवम्बर-नामदेव जयन्ती, (61) 22 नवम्बर-झलकारी जयन्ती, (62) 24 नवम्बर-गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस, (63) 27 नवम्बर-संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती (64) 3 दिसम्बर-विश्व विकलांग दिवस, (65) 4 दिसम्बर-दत्तात्रय जयन्ती/क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस, (66) 18 दिसम्बर-गुरु घासीदास जयन्ती, (67) 27 दिसम्बर-महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती, (68) 31 दिसम्बर-बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती. टीप - प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इन 68 ऐच्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन की छुट्टियाँ दी जायेंगी, उससे अधिक नहीं.

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।